एम/एस क्वालिटी इन साउथर्न स्टार

बनाम

क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारियों का राज्य

बीमा निगम

3 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948। 2 (22) सेवा शुल्क होटल के प्रबंधन द्वारा ग्राहकों की ओर से एकत्र किया गया प्रत्यक्ष सलाह के बदले में कर्मचारियों का भुगतान और बाद में उनके कर्मचारियों को भुगतान आयोजित किया गयाः मजदूरी का गठन नहीं करता है-ज्ञापन सं। पी-1/13/97-इन्स। IV दिनांकित 6.11.2002।

तत्काल मामले में विचार के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या होटल प्रबंधन द्वारा सेवा शुल्क एकत्र किया जाता है। ग्राहकों से और कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया की धारा 2 (22) के अर्थ के भीतर 'मजदूरी' की राशि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948।

ई. एस. आई. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवा शुल्क सीधे नहीं थे ग्राहकों द्वारा कर्मचारियों को भुगतान किया गया लेकिन बिलों का

हिस्सा था जिसे ग्राहक बिना किसी विकल्प के भुगतान करने के लिए बाध्य थे और इस प्रकार एकत्र की गई राशि का भुगतान किया गया या कर्मचारियों को समान रूप से वितरित किया गया तीन महीने में एक बार; और कि अपीलार्थी, तीन सितारा चल रहा है होटल के पास राशि के वितरण का पूर्ण नियंत्रण और शक्ति थी और इस प्रकार, 'टिप' से अलग था और इसके अंतर्गत था अभिव्यक्ति 'अतिरिक्त प्रतिपूर्ति'। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः उच्च न्यायालय के फैसले के बाद,

अभिनिर्धारित:

निगम ने पी-1/13/97 वाला एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया Ins.IV दिनांकित 6.11.2002 जिसमें कहा गया है कि सेवा शुल्क उनकी ओर से होटल के प्रबंधन द्वारा एकत्र किया गया

790 एम/एस क्वालिटी इन साउथर्न स्टार वी। आर. ई. जी. निदेशक, 791 कर्मचारी का राज्य INSU.CORPN। [पासायत, जे।]

कर्मचारियों को सीधे सुझावों के बदले में जो कर्मचारियों को भुगतान किया गया था बाद की तारीख को धारा 2 (22) के तहत मजदूरी नहीं माना जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948। ज्ञापन को देखते हुए जारी किया गया और साथियानाथन के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा

लिया गया दृष्टिकोण, ई. एस. आई. न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है। और अलग कर दिए जाते हैं। [पैरा 5,8 और 10]

साथियानाथन एन. एंड संस प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. ई. एस. आई. निगम और एन. आर., (2002)-II एल. एल. जे. 1002, अनुमोदित।

द रामबाग पैलेस होटल, जयपुर बनाम। द राजस्थान होटल श्रमिक संघ, जयपुर, [1976] 4 एस. सी. सी. 817 का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1250/2001

उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर 1992 के एम. एफ. ए. 1497 के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 29.7.1999 से।

अपीलार्थी के लिए श्याम दीवान, अखिल पाल छाबड़ा, सुधा मल्ला और राजन नारायण।

प्रत्यर्थी की ओर से सी. एस. राजन, वी. जे. फ्रांसिस और अनुपम मिश्रा।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. इस अपील में चुनौती है कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करना। आदेश के लिए चुनौती थी ई. एस. आई. में कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय (संक्षेप में 'ई. एस. आई. न्यायालय')

आवेदन No.123/89। अपील धारा 82 (2) के तहत दायर की गई थी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम')। आदेश पारित किया गया ई. एस. आई. न्यायालय अधिनियम की धारा 75 के तहत दायर याचिका पर था।

2. पृष्ठ भूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः प्रतिवेदिका पर प्रत्यर्थी द्वारा कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था।

ई. एस. आई. निरीक्षक द्वारा 9.1.1981 पर अपीलार्थी को योगदान करने के लिए बुलाना नवंबर, 1986 से नवंबर, 1987 की अवधि के लिए प्रीमियम प्रस्तावित, आदेश निर्धारित करने वाले अधिनियम की धारा 45-ए के तहत पारित किया गया था देय अंशदान की राशि। आदेश को अपीलार्थी [2007] 12 एस. सी. आर. द्वारा चुनौती दी गई थी। अधिनियम की धारा 75 के तहत एक आवेदन द्वारा। यह आवेदन था प्रत्यर्थी और ई. एस. आई. न्यायालय द्वारा विचाराधीन उसके सामने साक्ष्य लाया गया और यह माना गया कि धारा के तहत आदेश 45- अधिनियम में से ए को कोई कमजोरी नहीं थी।

3. अपीलार्थी के अनुसार, मूल प्रश्न यह था कि क्या होटल प्रबंधन द्वारा ग्राहकों से एकत्र किया गया सेवा शुल्क और कर्मचारियों के बीच वितरित की गई राशि के भीतर "मजदूरी" एक तीन सितारा होटल और प्रतिष्ठान इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। निर्विवाद रूप से, कुल बिल राशि का

10 प्रतिशत अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाता है। सेवा शुल्क और बिलों में शामिल किया जाता है। सेवा शुल्क इस प्रकार है एकत्र किए गए धन को अपीलार्थी के कर्मचारियों के बीच तिमाही आधार पर वितरित किया जाता है। सेवा शुल्क का संग्रह अनिवार्य रूप से वह है जिसे "सुझाव" कहा जाता है। और ग्राहकों के विकल्प पर भुगतान किया। ई. एस. आई. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवा शुल्क की प्रकृति, ये सीधे द्वारा भुगतान नहीं किए जाते हैं कर्मचारियों के लिए ग्राहक लेकिन बिलों का हिस्सा हैं जो ग्राहक बनाते हैं। बिना किसी विकल्प के भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और इस प्रकार एकत्र की गई राशि है तीन महीने में एक बार कर्मचारियों को समान रूप से भुगतान या वितरित किया जाता है। ई. एस. आई. न्यायालयक अनुसार अपीलकर्ताक लग पूर्ण नियंत्रण आ शक्ति छल। राशि के वितरण का और यह "टिप" से अलग है। यह अभिव्यक्ति द्वारा कवर की गई किसी भी घटना में व्यवहार किया गया था "अतिरिक्त प्रतिपूर्ति "। उच्च न्यायालय ने अपील में इस विचार को बरकरार रखा।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भुगतान समय-समय पर सभी कर्मचारियों के बीच समान रूप से वितरित किए जाते थे। तीन महीने। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सेवा शुल्क परिभाषित मजदूरी के दायरे से बाहर थे। संदर्भ दिया गया था द रामबाग पैलेस होटल, जयपुर बनाम में इस

न्यायालय के निर्णय के लिए। राजस्थान होटल श्रमिक संघ, जयपुर, [1976] 4 एस. सी. सी. 817। द. उच्च न्यायालय ने उसी धारणा को अलग किया कि यह "युक्तियों" से संबंधित है और इस पहलू पर कोई विचार नहीं किया गया था कि क्या इसे शामिल किया गया था अभिव्यक्ति "प्रतिपूर्ति"।

5. यह बताया गया कि उच्च न्यायालय का निर्णय था 29.7.1999 पर वितरित किया गया। इसके बाद ज्ञापन जारी किया गया। पी-1/13/97-Ins.IV दिनांकित 6.11.2002 वाला निगम स्पष्ट रूप से एम/एस गुणवत्ता इन साउथ स्टार v. आर. ई. जी. निदेशक, 793 कर्मचारी का राज्य INSU.CORPN। [पासायत, जे।] यह कहते हुए कि वर्तमान विवाद में शामिल प्रकृति के सेवा शुल्क वेतन का हिस्सा न बनें। यह भी बताया गया है कि मद्रास उच्च साथियानाथन एन. एंड संस प्राइवेट लिमिटेड में एक फैसले में अदालत। लिमिटेड और ओआरएस। वी. ई. एस. आई. निगम और एन. आर., (2002- II LLJ 1002) 6.2.2002 पर एक लिया अलग नज़रिया।

6. दूसरी ओर प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील ने समर्थन किया ई. एस. आई. न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश।

7. धारा 2 (22) मजदूरी को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

" मजदूरी का अर्थ है भुगतान या देय सभी पारिश्रमिक, किसी व्यक्ति को नकद में। कर्मचारियों या निहित, को पूरा किया गया था और इसमें (किसी कर्मचारी को अधिकृत छुट्टी, तालाबंदी की किसी भी अवधि के संबंध में कोई भी भुगतान, हड़ताल जो अवैध या छंटनी नहीं है और) अन्य अतिरिक्त

(क) नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन निधि में दिया गया कोई भी योगदान या

भविष्य निधि, या इस अधिनियम के तहतः

(ख) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;

(ग) विशेष भुगतान करने के लिए नियोजित व्यक्ति को दी गई कोई राशि।प्राकृतिक रोजगार द्वारा उस पर आने वाले खर्च; या

(घ) निर्वहन पर देय कोई उपदान "

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट परिपत्र इस प्रकार पढ़ता हैः

" ई सेवा शुल्क को निम्नलिखित के लिए "मजदूरी" में शामिल नहीं किया जा सकता हैः वहः

" सेवा शुल्क होटल के प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों की ओर से सीधे सुझावों के बदले में एकत्र किया जाता है और उसी का भुगतान किया जाता है।अपने कर्मचारियों के लिए। बाद की तारीख में।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2007] 12 एस. सी. आर. के रूप में एकत्र की गई ऐसी राशि।

'सेवा शुल्क' अधिनियम की धारा 2 (22) के तहत मजदूरी नहीं होगा।

ई. एस. आई. अधिनियम। ई. एस. आई. सी. के मामले में v. मेसर्स रामबाग पैलेस होटल, जयपुर। जयपुर उच्च न्यायालय ने माना है कि 'सेवा शुल्क' ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (22) के तहत मजदूरी नहीं है। यह फैसला जयपुर उच्च न्यायालय को ई. एस. आई. सी. में स्वीकार किया गया था और इसलिए सेवा शुल्क पर कोई योगदान देय नहीं है। (पहले के निर्देश पत्र सं. के माध्यम से जारी किया गया था। पी. 12/11/4 79 इन्स। डेस्क । डी. टी. डी. 18.9.79)"

9. 6.11.2000 दिनांकित ज्ञापन के परिचय में कहा गया है कि जारी किया गया क्योंकिः

" यह आवश्यक है कि इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश समय-समय पर न केवल समेकित किए जाते हैं बल्कि कुछ और आइटम भी होते हैं इसमें न केवल इस बात की शंकाओं को दूर करने के लिए शामिल किया गया है कि क्या हिस्सा है धारा 2 (22) के तहत मजदूरी के कुछ निर्देश जारी किए गए थे। इसके बजाय बहुत पहले-जैसा कि 1967 में था और कुछ निर्देश हैं आप में से कुछ क्षेत्रों में भी उपलब्ध नहीं है और इसे रखना मुश्किल है पुराने निर्देशों पर एक ट्रैक। उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और कुछ और वस्तुओं सहित समेकित निर्देश इस प्रकार हैं के अंतर्गतः " वे "मजदूरी" की प्रकृति में नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं दिया गया था रोजगार अनुबंध की शर्तों के तहत कर्मचारी, या तो व्यक्त या निहित। नियुक्ति पत्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कर्मचारी किसी अन्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। इस प्रकार यह सेवा शुल्क के वितरण को स्पष्ट रूप से इससे बाहर रखा गया है वेतन '।

10. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुएई मद्रास उच्च न्यायालय ने साथियानाथन के मामले में (ऊपर) के आदेश एस. आई. न्यायालय और उच्च न्यायालय को बनाए नहीं रखा जा सकता है और हैं धीरे-धीरे अलग कर दें।

11. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी दीपक कुमार (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।